633वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 अप्रैल 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 633वीं बैठक दिनांक 06/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9301/2022 M/S. B.C.C. Project Private Limited, Director, Shri Saurabh Bhardwaj, Kandil Bhavan, Baradari Chauraha, Ram Nagar Morar, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.425 ha. (90000 cum per annum) (Khasra No. 220, 219/3/2, 219/2, 216, 217) Village - Jigniya, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior, (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 220, 219/3/2, 219/2, 216, 217) Village - Jigniya, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior, (MP) 2.425 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 594वीं दिनांक 21/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 06/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप भारद्वाज (अधिकृत प्रतिनिधि) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण दिशा में कच्चा रोड़ है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर आबादी है। कच्चे रोड़ के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रोड़ से 10 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण को

नियंत्रण करने के उपाय, सिद्ध बाबा मंदिर तक मुरूम का रोड, मंदिर में वृक्षारोपण एवं पीने की पानी की व्यवस्था, आगनवाडी केंद्र, स्कूल, अस्पताल में सहयोग एवं खेल के मैदान का समतलीकरण इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –62 के सरल क्रमांक–01 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान का पूर्व दिशा में आंशिक भाग खुदा हुआ है तथा पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस संदर्भ में माईनिंग आफिसर से जानकारी चाही गई थी, जिसमें खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 629 दिनांक 05/04/23 के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदक मेसर्स बी.सी.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि. द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर उत्खनन् किया गया है तथा खनिज नियमानुसार विधि अनुकूल कार्यवाही की जा रही है । समिति ने पाया कि दोनों ही प्रोजेक्ट आवेदक मेसर्स बी.सी.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि. को आवंटित हैं तथा पूर्व प्रकरण क्रमांक 6114/2019 जो 1.599 हे. क्षेत्र में कार्यरत है सिया से ई.सी. प्राप्त है । समिति ने प्रकरण क्रमांक 6114/2019 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन हेतु परियोजना प्रस्तावक से जानकारी चाही तो ज्ञात हुआ कि आवंटित खनन् क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग का कार्य नहीं किया गया है, 03 रो प्लांटेशन भी नहीं किया गया है, (परियोजना प्रस्तावक को 03 वर्ष में 1500 पौधें लगाने थे जिसके संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 700–800 पौधें लगाये गये हैं), अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य नहीं किया गया है तथा सी.ई.आर. के तहत् उल्लेखित कार्य (राशि लगभग रू. 03.00 लाख) का ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं कर सके । चूँकि दोनों ही प्रकरणों में आवेदक एक ही है, अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्य पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है तथा उनको किए जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की है । परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि उनके द्वारा जून, 2019 के पश्चात् कितनी छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अनुशंसा की कि चूँकि दोनों ही प्रकरणों में आवेदक एक ही है, अतः वे पूर्व के प्रकरण क्रमांक 6114/2019 में जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें तथा किन परिस्थिति में आवंटित खनन् क्षेत्र के बाहर खनन् किया गया की प्रमाणिक जानकारी भी प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 29/06/19 के द्वारा जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्त क्रमांक–25 रिक्लेमेशन आफ साइट से यह स्पष्ट नहीं होता कि जो क्षेत्र खोदा गया है, उसका पुनरूद्धार कौन करेगा (परियोजना प्रस्तावक या खनिज विभाग) । इस शर्त पर तकनीकी रूप से विचार किया जाना चाहिए कि जो क्षेत्र खोदा गया है, उसके पुनरूद्धार हेतु मटेरियल कहॉ से आयेगा तथा उसके परिवहन में वाहनों के आवागमन से प्रदूषण बढ़ने की संभावना भी रहेगी ।

2. <u>प्रकरण क्रमांक 8995/2022 – श्री हितेंद्र प्रताप सिंह, लोधी सुभाष नगर हजीरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 388/1, रकबा 03.344 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–27,740 मी.^{3}, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईसागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 388/1, रकबा 03.344 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 554वीं दिनांक 23/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हितेंद्र प्रताप सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके उत्तर–पूर्व क्षेत्र से एच.टी. लाईन निकल रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एच.टी. लाईन के कारण आंवटित खनन् क्षेत्र में लाईन के दोनों ओर 50–50 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है, जिसमें कम ऊॅचाई के पौधों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र में से एक सरफेस रनऑफ ड्रेन भी निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसको गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के माध्यम से चेनलाईज किया जायेगा । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल छिडकाव, रोड का रखरखाव, वृक्षारोपण एवं आंगनवाडी केंद्र में सहयोग एवं मेडिकल केंप इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–42 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 01 जलाशय है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्लूआरडी/ जनपद पंचायत में उक्त विषय

विशेषज्ञ/सीजीडब्लूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट, टोटल वाटर होल्डिंग केपेसिटी एवं इसका भविष्य में कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

3. <u>प्रकरण क्रमांक 8978/2022 – श्री हेमंत कुमार, ग्राम – गहोरा, तहसील – ईशगढ़, जिला – अशोकनगर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 27,075 मी.^{3}, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईसागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र में 10 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है तथा उनके एवज् में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । आवंटित क्षेत्र का वह भाग जहॉ अधिक संख्या में पेड़ लगे हैं, उसे नॉन माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है और वहॉ खनन् प्रस्तावित नहीं है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय, सिद्ध बाबा मंदिर की वाऊंड्रीवाल, वृक्षारोपण एवं सड़क का रखरखाव इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–42 के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिण दिशा में 133 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण–पूर्व में 145 मीटर पर जल संरचना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों

के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्लूआरडी/जनपद पंचायत में उक्त विषय विशेषज्ञ/सीजीडब्लूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट तथा टोटल वाटर होल्डिंग केपेसिटी इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

4. <u>Case No 9791/2023 Smt. Sadhna Sharma W/o Shri Sanjay Sharma, Owner, M/s Om Shri Stone Crusher, R/o Hall-117, Garden Home Face-3, Alkapuri, District- Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Gangapur Stone Quarry in an area of 1.220 ha. (90000 Cum per annum) (Khasra No. 11/1/1 & 11/2/1) Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 11/1/1 & 11/2/1) Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 1.220 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती साधना शर्मा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 316 दिनांक 10/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके उत्तर पूर्वी दिशा मे 130 मी. पर नहर, 110 मीटर पर आवास/आबादी एंव 120 मी. पर कच्चा रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 316 दिनांक 10/02/23 के अनुसार प्रस्तावित खदान जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में शामिल की जायेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उत्तर–पूर्वी दिशा मे 110 मीटर पर आवास/आबादी के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है किंतु आवंटित खनन् क्षेत्र के पास आवास / आबादी होने के कारण खनन् कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा, जिसका शपथ–पत्र वे प्रस्तुत कर देंगे।

इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें मार्च, 20 से कार्य किया जाना गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित हो रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको इसी स्थिति में नवम्बर, 2022 में आवंटित हुई है तथा पुराने पिट के विवरण (पिट साईज 3550 X 02 मीटर) अनुमोदित खनन् योजना में तथा सरफेस मेप पर दिखाया गया है। चूँकि खदान निजी भूमि पर आवंटित है, अतः यह सत्यापित किया जाना आवश्यक है कि आवेदक ने यह खदान कब क्रय की, यदि आवेदक द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात् पिट निर्मित हुआ है तो प्रकरण वॉयलेशन का होगा । अतः परियोजना प्रस्तावक यह प्रमाणिक जानाकरी (भूमि की रजिस्ट्री) प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा यह निजी भूमि कब क्रय की गई ।

5. <u>Case No 9793/2023 Smt. Ritu Shridhar, Lease Owner, R/o Kishanpuri, District-Jhabua (MP)-457661, Prior Environment Clearance for Piliya Khadan Stone Mine in an area of 2.00 ha. (5320 Cum per annum) (Khasra No. 822/3 Govt.) Village-Piliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 822/3 Govt.) Village-Piliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ऋतु श्रीधर (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 140 दिनांक 06/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.99 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके दक्षिण–पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर पक्का रोड़, पूर्वी दिशा में 70 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर औद्योगिक गतिविधियॉ, पश्चिम दिशा में 220 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 600 मीटर पर जल रोकने की संरचना एवं 25 मीटर की दूरी पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मौसमी नाले के संरक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण में 25 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है तथा गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 140 दिनांक 06/02/23 के अनुसार प्रस्तावित खदान संपूर्ण स्वीकृति प्राक्रिया हो जाने के पश्चार्त जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में शामिल की जायेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय

संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5320 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.85 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.74 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम पिलिंया के शासकीय प्राथमिक शाला में 1 कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेबल, के साथ और 1 आलमारी लाइब्रेरी के लिये दी जायेगी।	**60,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**
1.	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सफेद कस्टार,सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3.	पिलिंया खदान ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि ।	1280
4.	शासकीय विद्यालय पिलिंया खदान में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, अशोक, नीम, मोलश्री, गुलमोहर।	20
5.	पिलिंया खदान ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि ।	1280
		योग	2400

6. **Case No 9798/2022 M/s SHRI BALAJI CRUSHER AND DEVELOPERS, Prop. Shri Umesh Mishra, R/O -02 JAGDAMBA NAGAR DISTRICT-KHANDWA, M.P. Prior Environment Clearance for at 1.74 Ha. Stone – 24,000 m3/year (Gitti - 12,000 m3/year & M-Sand -12,000 m3/year) at khsasra 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 (Private) Village UCHHAYAN Tehsil Khandwa District Khandwa (M.P.)**

This is case of Stone Mine & M-Sand. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site khsasra 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 (Private) Village UCHHAYAN Tehsil Khandwa District East Nimar (M.P.) 1.74 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश मिश्रा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1501 दिनांक 15/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.38 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके दक्षिण दिशा मे 180 मी. पर कच्चा रोड है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1501 दिनांक 15/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जबकि अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान परिलक्षित हो रही है, जिनका विवरण एकल प्रमाण पत्र में नहीं दिया गया है। अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी से उपरोक्त संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करवाते हुए जानकारी प्राप्त की जाये।

7. **Case No 9784/2023 Shri Abhishek Singh, Owner, R/o Rajendra Nagar, Gali No. 5, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Bandhi Mohar Murrum Quarry in an area of 1.900 ha. (17400 Cum per annum) (Khasra No. 1863 Govt.) Village-Bandhi Mohar, Tehsil-Uchera, District-Satna (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1863 Govt.) Village-Bandhi Mohar, Tehsil-Uchera, District-Satna (MP) 1.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

633वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 अप्रैल 2023

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2241 दिनांक 23/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.70 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्व दिशा मे 110 मी. पर तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 120 मी मीटर पर आबादी, उत्तर–पश्चिम दिशा में 120 मीटर तथा पूर्व दिशा में 240 मीटर पर जल रोकने की संरचना तथा उत्तर और पश्चिम दिशा में कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, जल रोकने की संरचना के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है तथा कच्चे रोड़ के कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में 10 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदित खनन् क्षेत्र में एवं उसके आसपास कंटूर ट्रेंचेस खुदे हुए है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा खनिज की उपलब्धता को देखते हुए तथा ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/21 के अनुमोदन उपरांत उक्त खदान स्वीकृत की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज निकालने के पश्चात् जो पिट निर्मित होगा, वह आसपास के क्षेत्र हेतु ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज का कार्य करेगा ।

कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2240 दिनांक 23/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारणा मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 17,400 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.84 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम बंधी मोहर के आंगनबाड़ी एवं शाशकीय माध्यमिक शाला की मरम्मत एवं पुताई करवाने हेतु	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	चिरोल, नीम, खमेर, जंगल जलेबी एवं बांस इत्यादि	500
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)	कदम, नीम, शीशम, करंज, जामुन, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री गार्ड के साथ-	400
3.	स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी प्रांगण	नीम कदम, पीपल एवं अशोक इत्यादि	100
4.	ग्राम वासियों में वितरण	आम , मुनगा, कटहल नीबू, जामुन नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	1200
		योग	2200

8. <u>Case No 9777/2023 Shri Pavan Kumar S/o Shri Amratlal Singh Yadav R/o Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Jigani Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2200 Cum per annum) (Khasra No. 2377, 2388 Pvt. land) Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2377, 2388 Pvt.) Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कश्यप) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 20/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि दोनों क्षेत्र के बीच से एक छोटी नहर निकल रही है जो डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल है जो वर्तमान उपयोग में नही है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मिट्टी का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् की अधिकतम् गहराई 02 मीटर होगी, जो मैन्युअली किया जावेगा । समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के दक्षिण दिशा से 10 मीटर तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा से 20 मीटर की दूरी पर नहर (डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल) है जिसे नाले के समतुल्य मानते हुए 50–50 मीटर सेट बेक छोडा जाना चाहिए, आवंटित खनन् एक भाग में क्लिंन स्थापित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी क्लिंन है जिसका उपयोग ईटो को पकाने में किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में सिर्फ पुरानी क्लिंन स्थापित है तथा स्वाईल माईनिग का काम नही किया गया है अतः प्रकरण वायलेशन का नही है । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 15 एंव सरल क्रमांक 25 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के दक्षिण दिशा से 10 मीटर तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा से 20 मीटर की दूरी पर नहर (डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल) है अतः 50–50 मीटर सेट बेक छोडते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
2. स्थापित क्लिंन में कौन सा ईधन उपयोग में लाया जायेगा ।
3. प्रस्तावित ईधन का सोर्स क्या है ।
4. ईट बनाने के दौरान उपयोग में आने वाला पानी कहां से प्राप्त किया जायेगा ।
5. ईधन के जलाने से जो राख उत्पन्न होगी उसका निष्पादन कैसे किया जायेगा ।

9. <u>Case No 9782/2023 Shri Mahavir Singh, Owner, R/o Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal, District-Morena (MP)-476444, Prior Environment Clearance for Girgoni Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2100 Cum per annum) (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री महावीर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1230 दिनांक

24/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि दोनों क्षेत्र के बीच में क्लिंन स्थापित है, जिसमें इस खदान से निकलने वाली मिट्टी द्वारा निर्मित ईटों को पकाया जायेगा। समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के पूर्वी दिशा में 10 मीटर की दूरी कच्चा रोड़ तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा में 320 मीटर पर आबादी है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मिट्टी का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् की अधिकतम् गहराई 02 मीटर होगी, जो मैन्युअली किया जावेगा । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 21 एंव सरल क्रमांक 36 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. स्थापित क्लिंन में कौन सा ईधन उपयोग में लाया जायेगा ।
2. प्रस्तावित ईधन का सोर्स क्या है ।
3. ईधन के जलाने से जो राख उत्पन्न होगी उसका निष्पादन कैसे किया जायेगा ।
4. ईट बनाने के दौरान उपयोग में आने वाला पानी कहां से प्राप्त किया जायेगा ।
5. खनन् की गहराई 2.5 मीटर हेतु स्पष्टीकरण ।

10. <u>Case No 9788/2023 Shri Sandeep Mandhwani, Director, M/s Shiv Lalji Construction LLP R/o 07/1st floor, Om Construction Gulmarg Complex, Sapna Sangeeta Road, Indore (MP)- 452001, Prior Environment Clearance for Veda Commune (Commercial Project) [Total Plot Area-10560.85 sqm, Total Built-up Area-59725.15 sqm] at (Khasra No. 69), Scheme No-151 & 169B (Super Corridor), Village-Bhawarsala, Tehsil-Sanwer, District-Indore, (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Veda Commune (Commercial Project) [Total Plot Area-10560.85 sqm, Total Built-up Area-59725.15 sqm] at (Khasra No. 69), Scheme No-151 & 169B (Super Corridor), Village-Bhawarsala, Tehsil-Sanwer, District-Indore, (MP).

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and Shri Sandeep Mandhwani, Director, M/s Shiv Lalji Construction, Indore wherein following details were submitted:

S.No.	Information Required	Details

1.	Project Proposal	Proposed New commercial building "Veda Commune by M/s Shiv Lalji Construction LLP " at Plot No. D-69, Scheme No-151 & 169 B (Super Corridor) Indore, Madhya Pradesh-453112.
2.	Total Plot Area	10560.85 sq.mt.
3.	Total Built up Area	59725.15sq.mt.
4.	Diesel power generating capacity (power backup)	320 KVA x 03
5.	Water requirement	Total water requirement: 164.50 KLD Fresh water requirement: 81.14 KLD Total recycled water generated: 119.69 KLD Flushing Purpose: 68.08 KLD Green Belt: 15.28 KLD Sewer Line: 36.33 KLD
6.	Rainwater harvesting details	Recharge pits (existing & proposed): 03 nos Total recharge capacity: 67.27 m^3/hr
7.	STP details	Capacity: 150 KLD Type of technology: MBBR
8.	Solid waste generation (kg/day)	Total solid waste: 929.80 Kg/Day Organic: 536.88 Kg/Day Non-organic: 268.44 Kg/Day Inert: 89.48 Kg/Day E-waste: 403.20 KG/Annum
9.	Plantation	Trees to be planted: 106 nos Green area: 1056.00 m^2 % in terms of total plot area: 10.00 %
10.	Parking	Total parking (ECS): 443 nos Basement: 417 ECS Stilt: 00 nos Open: 26 nos
11.	Remediation cost (If any)	Nil
12.	EMP	Capital: 2.54 Cr Recurring: 0.58 Cr
13.	CER	1,50,00,000 INR
14.	Any other important issue	No

During presentation, PP submitted that there will be a no change in the land use as the proposed land area is already earmarked for commercial development as per Indore Development Plan 2021. Land is in already in their possession. All construction activities will be confined within the project premises and there will be no physical changes outside the construction area boundary. The impact due to the proposed project will be increase in the traffic load, noise levels and dust emission emanating from various construction activities and equipments. Due care will be taken during construction as well as operational phase to minimize the impact on surroundings such as shielding of construction site, wetting of roads and stockpiles etc. Development and construction of proposed project will

be done as per applicable norms/byelaws and building codes. Total estimated quantity of earth work is approx. 51,143.48 m3. It is estimated that approximately 51,143.48 m3 of earth material will be excavated during initial construction phase for foundations and out of which approximately 80-90 % materials shall be reutilized into backfilling and leveling. However, the top soil will be stored in temporary constructed soil bank properly covered by tarpaulin sheets and then reused for landscaping of the proposed commercial project. During construction phase, about 100 KLD water will be required and water supply will be met through tankers. Sewage generated from the construction workers will be disposed by channeling it through the Mobile STP. Recyclable waste will be sold out to the authorized recycler. During presentation PP submitted that 03 star GRIHA certification will be obtained for this project. During presentation PP submitted that IDA has obtained EC for area development of this Super Corridor Project (Case No. 5516/2016) and infrastructure development facilities such as surrounding roads etc are developed by IDA. During presentation committee observed that some of the infrastructure facilities mentioned in their EC such as CETP is yet developed or not should be enquired for IDA. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed new commercial building project "Veda Commune" by M/s Shiv Lalji Construction LLP Plot No. D-69, Scheme No-151 & 169 B (Super Corridor) Indore Madhya Pradesh, (Total Plot Area = 10560.85 sqm, Total Built up Area = 59725.15 sqm) at Plot No. D-69, Scheme No-151 & 169 B (Super Corridor) Indore Madhya Pradesh. Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. 03 Diesel power generating sets 320 kVA * 03 nos. are proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG sets 320 kVA * 03 nos. shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 164.50 KLD out of which 81.14 KLD is fresh water requirement and 119.69 KLD will be the total recycled water generated, out of which 68.08 KLD recycled water will be used for flushing and 15.28 KLD water will be used for horticulture.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for

ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 03 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 67.27 m3/hr .Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity **- 150** KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 150 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
iv. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. **Waste Management**

i. Total waste 1560 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 536.88 Kg/day and non- organic waste 268.44 Kg/day), Inert waste 89.48 Kg/day, E-waste 403.20 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total 106 trees shall be planted in the area of 1056 m^2 (10% of total plot area) which is developed as greenbelt development as follows:

Sr. No.	Local Name	No. of trees
01	Putran jeeva	10
02	Amaltas	10
03	Ficus benjamin	10
04	Gulmohar	20
05	Ashoka	20
06	Sita Ashok	21
07	Kanak Champa	05
08	Neem	10

ii. Not tree will be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for 443 ECS (Basement parking 417 ECS & open parking 26 ECS).

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporation Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be

reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 2.54 Cr as capital and Rs. 0.58 Cr as recurring cost for this project.

vi. For this project PP has proposed Rs. 150 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:

S.No.	Activity	1st Year (Rs Lakhs)	2nd Year (Rs Lakhs)	3rd Year (Rs Lakhs)	Total Cost (Rs Lakhs)
1.	Habitat Development and staff welfare of Ralamandal Wildlife sanctuary, Indore.	05.00	05.00	05.00	15.00
2.	Providing need based medical equipments such as ECG Machines (05/year), BP Monitors (05/year), Sugar Testing Machines (10/year) Weighing Scales (05/year), Advance Patient Beds (10/year), Fridge (02/year), Coolers (10/year), Ceiling Fans (10/year), Wheel Chairs (10/year), Stretchers (10/year), OT Equipments/Materials (LS), Pathological Lab Facilities, Office Equipments (such as tables, Chairs-LS) to PHC, Pedmi.	15.00	10.00	10.00	35.00
3.	Providing need based medical support for Vetinary Sub-Centre Hospital	05.00	05.00	05.00	15.00
4.	Fodder & tree species plantation, Vaccination, New Bore wells, Solar lights, RWH pits and need base development of other facilities at Pedmi Gaushala, Devi Ahilyabai Trust, Indore. (Minimum 03 times)	10.00	10.00	10.00	30.00
5.	Organizing medicals camps (such as for oral health, dental checkups with distribution of medicines) and Vetinary Health Camps at Village Pedmi, Jaitpura, Teliakhedi, Udail, Samiliya Raimal, Khandel, Kharadiya, Dhobghata, Magaradeh, Nahar Jhabua, Janpav and Dongarkheda.	07.00	07.00	06.00	20.00
6.	Organizing Vetinary Health Camps at Village Pedmi, Jaitpura, Teliakhedi, Udail, Samiliya Raimal, Khandel, Kharadiya, Dhobghata, Magaradeh, Nahar Jhabua, Janpav and Dongarkheda.	05.00	05.00	05.00	15.00

7.	Development and maintenance of talabs and green cover (city forest) in Indore in consultation with Nagar Nigam.	10.00	10.00	10.00	30.00
	Total	50.00	50.00	50.00	150.00

vii. **XI. Miscellaneous**

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

11. <u>Case No 9772/2023 Shri Ashish Sharma, Owner, R/o Village-Ghoghar, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) Prior Environment Clearance for Kutarhia Flagstone Quarry in an area of 2.00 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 299 Govt.) Village- Kutarhia, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 299) Village- Kutarhia, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1800 दिनांक

26/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके दक्षिण–पूर्व दिशा मे 100 मी. पर पक्का रोड है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लैग स्टोन के खनन् का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पिट दिख रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है, जिसे हमने अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप दिखाया गया है तथा यह खदान अक्टूबर, 2022 में आवंटित हुई है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के आस–पास कुछ पुराने पिट दिख रहे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस संदर्भ में खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई है जिसमें खनिज अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 429 दिनांक 05/4/23 के माध्यम से सूचित किया है कि आवंटित खनन् क्षेत्र के आस–पास जो गढढे दिख रहे है वह स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अपने उपयोग के लिये निकाले गये पत्थरों के कारण दिख रहे है कोई अन्य खदान् स्वीकृत नही है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना ने पत्र क्रमांक 1802 दिनांक 26/02/2022 के द्वारा सूचित किया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016–17 में बनी है, नवीन जिला सर्वेक्षण रिपेार्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 1500 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.89 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
कुठरहिया प्राथमिक स्कूल में 25 टेबल – चेयर के सेट दिये जाऐगें।	75000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
		योग	2400

12. <u>Case No 9789/2023 Shri Sachin Dungarwal, Owner, R/o 519 Ringnod, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)-457336, Prior Environment Clearance for Jhalava Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 1119, 1129 Govt.) Village-Jhalava, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1119, 1129 Govt.) Village-Jhalava, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन डोगरवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 492 दिनांक 01/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा (240 मीटर) एवं उत्तर–पश्चिम दिशाा (320 मीटर एवं 150 मीटर) में विंड मिल स्थापित हैं, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि विंड मिल के संबंध में कार्यपालन यंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, भोपाल ने पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 06/03/23 के माध्यम से विंड मिल के 160 मीटर दूर होने के कारण नॉन ब्लास्टिंग की स्थिति में अनापत्ति दी है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में क्रमशः 230 मीटर एवं 390 मीटर पर तालाब तथा पूर्व दिशा में 60 मीटर पर अर्दन चेक डेम है, जिसके संदर्भ में परियोजना

प्रस्तावक ने बताया कि इनके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक बनाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 05 पेड लगे है जिनमें से कोई भी नही काटा जायेगा । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक 492 दिनांक 01/03/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.20 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.14लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम झलावा में सरपंच महोदय के परामर्श से 02 हेक्टेयर की उपयुक्त भूमि पर चरागाह का निर्माण किया जावेगा ।	15,000
ग्राम झलावा के शासकीय प्राथमिक शाला में 10 बेंच डेस्क एवं 01 ब्लैकबोर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा ।	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, सीताफल, चिरोल* आदि।	600
2	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–*सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम , महुआ* आदि।	220
3	**ग्राम झालावा के नजदीक स्थित शमशान घाट के परिसर में**	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *पुत्रंजीवा, मोलश्री, नीम, पीपल, मुनगा, आम, करंज, बरगद, चिरोल* आदि।	80

4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, मुनगा* आदि।	1500
		योग	2400

13. <u>Case No 9778/2023 Shri Anil Devatwal, Lessee, R/o Annapurna Colony, Mhow, District-Indore (MP), Prior Environment Clearance for Mohida Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 39 Govt.) Village-Mohida, Tehsil-Maheshwar, District-Khargone (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 39 Govt.) Village-Mohida, Tehsil-Maheshwar, District-Khargone (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 9617 दिनांक 27/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिमसें कंटूर ट्रेंचेज बने है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा खनिज की उपलब्धता को देखते हुए तथा ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 16/08/21 के अनुमोदन उपरांत उक्त खदान स्वीकृत की गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज निकालने के पश्चात् जो पिट निर्मित होगा, वह आसपास के क्षेत्र हेतु ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज का कार्य करेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 550 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पूर्व दिशा में 270 मीटर पर आबादी तथा पश्चिम दिशा में 150–200 मीटर पर नदी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड लगे है जिनके बेरियर जोन में होने के कारण काटा जाना प्रस्तावित नही है ।

कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 9615 दिनांक 27/02/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक मंजूरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है, जिससे कि उक्त उत्खनिपट्टा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया

है । उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला में 5000 लीटर क्षमता कि पानी की टंकी लगवाई जावेगी एवं वह पर टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जावेगी साथ ही उक्त विद्यालय की पुताई करवाई जावेगी	30000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *बबूल, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू ,खमेर सफेद कैस्टर, करंज* आदि।	270
2	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *नीम, पीपल, करंज, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू* आदि।	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल मुनगा* आदि।	780
		योग	2400

14. <u>Case No 9787/2023 Shri Pawan Kumar Agrawal, Director, M/s Pawsun Minerals and Coal Benefication Private Limited R/o Flat No. 105A, Bashed Ahmed Complex, Link Road, Bilaspur (CG)- 495001, Prior Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 10.71 ha. (Khasra No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31) Village-Gareriya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 10.71 ha. (Khasra No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31) Village-Gareriya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP).

The case was presented by the PP shri Pawan Kumar Agrawal and their consultant Shri S.R.D. Nagarjuna, M/s Pioneer Enviro Laboratories and Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad wherein PP submitted that proposed project is located at Gaderiya Village, Singrauli Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh and land is allocated to M/s. Pawsun Minerals & Coal Benefication Pvt. Ltd. by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) for industrial purpose. Total land identified for the proposed project is 10.71 Ha. &Khasra nos. of total land are 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30 & 31. Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 06.03.2023. Connecting road to NH # 39 is passing through the part of project site, splitting project site into two part i.e. 10.05 Ha. & 0.66 Ha., 10.05 Ha. of land will be used for process units and 0.66 Ha. of land will be used for Truck Parking. As proposed land is Govt. allotted land, no alternate sites have been identified for the proposed project. During presentation, following details were submitted by PP:-

S.No.	Salient Features / Environmental features	Distance w.r.t. site / Remarks
1	Type of Land	Govt. Land (allocated by MIDC)
2	National Park/ Wild life sanctuary / Biosphere reserve / Tiger Reserve / Elephant Corridor / migratory routes for Birds	There are no notified National Park/ Wild life sanctuary / Biosphere reserve / Tiger Reserve/ migratory routes for Birds with in 10 Km. radius of the plant.
3	Historical places / Places of Tourist importance / Archeological sites	Nil
4	Critically polluted area as per MoEF&CC Office Memorandum dated 13th January 2010	Nil. And also the Plant area does not fall in the areas given in Hon'ble NGT order issued vide dated 10th July 2019.
5	Nearest Village	Kanai Village (0.3 Kms.)
6	Forests	Teldah PF (NE Direction, 0.3 Kms.), Parhari PF (E Direction, 2.6 Kms.), Chokra PF (SE Direction, 6.0 Kms.), Orgari PF (N Direction, 6.7 Kms.), Uska PF (NE Direction,

S.No.	Salient Features / Environmental features	Distance w.r.t. site / Remarks
		8.2 Kms.), Mohanban RF (South Direction, 2.7 Kms.), Muher RF (SE direction, 6.75 Kms.),
7	Water body	Kanchan Nallah (South Direction, 2.5 Kms.) Manihari Reservoir (SW Direction, 2.7 Kms.)
8	Nearest Highway	NH # 75 (Adjacent to the project site) is being converted to Major District Road
9	Nearest Railway Station	Bargawan Railway Station – 3.7 Kms. (by Road)
10	Litigation / court case is pending against the proposed project / proposed site and or any direction passed by the court of law against the project	Nil

During presentation, PP submitted that washery will have single module of 2.48 MTPA capacity based on wet separation process comprising crushing, screening, washing and handling. The heavy media cyclone is an extremely efficient coal cleaning technology. ROM coal is subjected to closed circuit crushing & screening to obtain (-) 50 mm size fraction. Feed coal processed in heavy media cyclone. Magnetite and water are used as the media. The media density primarily determines separating gravity. A gravimetric separation takes place. Buoyancy affect of the media forces the lighter coal solids to the center of the cyclone where they are transported upward. The dense mineral matter spirals towards the apex and exits through orifice. Clean coal and rejects are produced from the cyclone. Magnetite carried away by the coal particles is recovered by water spraying and reused. Entire process wastewater is recycled in the washing circuit as such no effluent discharge is envisaged. (Closed circuit loop will be maintained) and there will not be any process waste water will be generated in the proposed Wet type coal washery and Zero effluent discharge will be maintained. However, sanitary waste water will be treated in STP of suitable capacity. The ROM coal from mines mainly Singrauli Coal Fields areas will be transported through road by covered trucks up to the proposed site. Railway siding is not available at the site. Washed coal from the plant will be transported by road (well connected to National Highway # 75) in covered trucks directly to the customer (or) by road up to nearest Railway Station (Bargawan RS – 3.7 Kms.) and from there by rail to the customer. Washery rejects from the plant will be transported by road (well connected to National Highway # 75) in covered trucks directly to the customer (or) by road up to nearest railway station (Bargawan RS – 3.7 Kms.) and from there by rail to the customer. Water requirement for the proposed project is 620 KLD (600 KLD for Process and 20 KLD for Domestic purpose). Water required will be sourced from the Ground water for which application has been made for permission to Central Ground Water Authority vide application no. 21-4/1760/MP/IND/2023.

During presentation it was observed by the committee that allotted area is in two parts for which PP submitted that a connecting road to NH # 39 is passing through the part of project site, splitting project site into two part i.e. 10.05 Ha. & 0.66 Ha. Hence, 10.05 Ha. of land will be used for process units and 0.66 Ha. of land will be used for Truck Parking. Committee suggested that area left for truck parking shall be developed as model rest shelter for truck drivers having all essential facilities such as wash rooms, rest rooms and canteen. All around of this area thick green belt shall be developed. No trucks/vehicles connected to this project shall be parked outside of the project area or on roads. Application for GW withdrawal has been made vide application No. 21-4/1760/MP/IND/2023. Number of houses is in existence within the allotted lease area for which PP submitted that they will be submitted with EIA report. A pucca road is in existence of the site on the southern side thus its protection plan shall be discussed in EIA report. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

i) Allotted area is in two parts and a connecting road to NH # 39 is passing through the part of project site, splitting project site into two part i.e. 10.05 Ha. & 0.66 Ha. Hence, 10.05 Ha. of land is proposed to be used for process units and 0.66 Ha. of land for Truck Parking. Area left for truck parking shall be developed as model rest shelter for truck drivers having all essential facilities such as wash rooms, rest rooms and canteen, all around of this area thick green belt shall be developed and no trucks/vehicles connected to this project shall be parked outside of the project area or on roads for which detail proposal shall be submitted with EIA report.
ii) Number of trees is within the allotted area thus their inventory wrt to girth, height, species & their respective number and management plan shall be submitted with the EIA report.
iii) Number of houses is in existence within the allotted lease area for which detailed R&R plan shall be discussed in the EIA report.
iv) A pucca road is in existence of the site on the southern side thus its protection plan shall be discussed in EIA report.
v) The proposed coal washing technology shall be discussed in detail in the EIA report. The washing technology so chosen should conform to 'Zero Liquid Discharge'.
vi) Clarification from forest department that allocated area does not fall under elephant movement area.
vii) Impact Assessment Study of the area shall be carried over by project proponent considering Ecological service system amd loss to be assessed regarding flora and fauna.

viii) For proper baseline air quality assessment, Wind rose pattern in the area should be reviewed and accordingly location of AAMSQ shall be planned by the collection of air quality data by adequate monitoring stations in the downwind areas. Monitoring location for collecting baseline data should cover overall the 10 km buffer zone i.e. dispersed in 10 km buffer area.

ix) Project proponent to prepare Environmental Cost Benefit Analysis for the project in EIA/EMP Report.

x) Permission for ground water withdrawal shall be obtained from Central Ground Water Authority (CGWA).

xi) Impact of proposed project/activity on hydrological regime of the area shall be assessed and report be submitted. Hydrological studies as per GEC 2015 guidelines to be prepared and submitted.

xii) Heavy metals including other parameters in surface water quality shall be analyzed and provided in EIA Report.

xiii) The parameters Arsenic, Lead and Silica shall also be analyzed in ambient air quality.

xiv) PP shall submit details of implementation of laying conveyor belt for transportation of coal from nearest mine to the washery. PP shall provide the plan for reduction of number of trucks for transportation of coal and fleet to be redesigned.

xv) PP shall work on the layout and sitting of washery so that coal storage area, crushing units and rejects storage area shall not be near the villages or cause any pollution to agricultural land.

15. <u>Case No 9605/2023 Shri Samrat Saraswar, Lessee, R/o Ward No. 27, Circuit House Road, District-Balaghat (MP)-481001, Prior Environment Clearance for Akola Crusher Stone Mine in an area of 1.620 ha. (16800 cum per annum) (Khasra No. 516), Village-Akola, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP)</u>

This is case of Crusher Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 516), Village-Akola, Tehsil-Kirnapue, District-Balaghat (MP) 1.620 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वी बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

633वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 अप्रैल 2023

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सम्राट सरस्वर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 18/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार कच्चा रोड़ खदान के पूर्व दिशा में लगभग 30 मीटर, उत्तर दिशा में 115 मीटर, पश्चिम दिशा में 85 मीटर तथा पूर्वी भाग में से होकर निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत किया जाये। एकल प्रमाण पत्र एवं साथ में संलग्न वन मंडलाधिकारी के पत्र दिनांक 14/09/22 अनुसार प्रश्नाधीन खदान वन क्षेत्र से 80 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संदर्भ में संभागीय आयुक्त समिति से उनकी बैठक दिनांक 21/02/19 अनुमति प्राप्त है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) फॉरेस्ट लेयर के अनुसार यह खदान वन क्षेत्र लगभग 80 मीटर की दूरी पर आ रही है । समिति की अनुशंसा है कि संभागीय आयुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओ के पालनार्थ आने वाले खर्चो का व्योरा ई.एम.पी. में शामिल कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–37 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार कच्चा रोड़ खदान के पूर्व दिशा में लगभग 30 मीटर, उत्तर दिशा में 115 मीटर, पश्चिम दिशा में 85 मीटर तथा पूर्वी भाग में से होकर निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

3. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. एकल प्रमाण पत्र एवं साथ में संलग्न वन मंडलाधिकारी के पत्र दिनांक 14/09/22 अनुसार प्रश्नाधीन खदान वन क्षेत्र से 80 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संदर्भ में संभागीय आयुक्त समिति से उनकी बैठक दिनांक 21/02/19 अनुमति प्राप्त है, अतः संभागीय आयुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओ के पालनार्थ आने वाले खर्चो का व्योरा ई.एम.पी. में शामिल कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

16. <u>Case No 9561/2022 M/s Rana Chemicals & Marble Pvt. Ltd., Lessee, Shri Vivek Singh Saraswar, Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP)-481001 Prior Environment Clearance for Bahiyatikur Manganese Mine in an area of 4.200 ha. (5000 TPA) (Khasra No. 143/1, 144/1, 232/1, 233/4 etc), Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP)</u>

This is case of Manganese Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 143/1, 144/1, 232/1, 233/4 etc), Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP) 4.200 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

633वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 अप्रैल 2023

प्रकरण सेक की पूर्व 623वी बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विवेक सिंह सरस्वर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसका रकबा 4.20 हे. है तथा खनन् मुख्य अयस्क–मैग्नीज का है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। डी.एफ.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 4423 दिनांक 07/8/20 के अनुसार आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण /वन क्षेत्र की निर्धारित सीमा से बाहर है । अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य ओपन कास्ट–सेमीमेकेनाइज्ड विधि से 6.0 मीटर की गहराई तक किया जायेगा जिसमें खनन् के दौरान मफल–कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाना प्रस्तावित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 105 मीटर, दक्षिण दिशा में 230 मीटर, उत्तर एवं पश्चिम दिशा में 75 मीटर की दूरी पर रोड़ है, उत्तर–पूर्व दिशा में 75 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 725 मीटर, उत्तर दिशा में 360 मीटर तथा पूर्व दिशा में 585 मीटर पर तालाब है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा दक्षिण दिशा में खदान के समीप स्थित कुछ कच्चा निर्माण दिख रहा है जिनके बारे में संपूर्ण विवरण ई. आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। आवेदक को खनन् क्षेत्र 2010 में आवंटित हुआ तब से अभी तक कोई कार्य किया गया या नही उसका विवरण संपूर्ण क्रोनोलॉजी के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 105 मीटर, दक्षिण दिशा में 230 मीटर, उत्तर एवं पश्चिम दिशा में 75 मीटर की दूरी पर रोड़ है, उत्तर–पूर्व दिशा में 75 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 725 मीटर, उत्तर दिशा में 360 मीटर तथा पूर्व दिशा में 585 मीटर पर तालाब है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा दक्षिण दिशा में खदान के समीप स्थित कुछ कच्चा निर्माण दिख रहा है जिनके बारे में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवेदक को खनन् क्षेत्र 2010 में आवंटित हुआ तब से अभी तक कोई कार्य किया गया या नही उसका विवरण संपूर्ण क्रोनोलॉजी के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये ।

4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

17. <u>Case No 9776/2023 Shri Rajasahab Bundela S/o Shri Jeevan Singh Bundela, R/o Ubari, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)-473995, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 4.00 ha. (5,040 Cum per annum) (Khasra No. 406 Govt.) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 406 Govt.) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजासाहब बुंदेला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 14/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्व दिशा में 130 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 150 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 25 मीटर पर शेड तथा पूर्व दिशा में 340 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर क्रेशर / प्लांट स्थापित हैं, अतः इसका संपूर्ण विवरण तथा इसके भविष्य में उपयोग के बारे में जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.

आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया कार्यालय में अपने पत्र दिनांक 19/12/22 के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदित खदान का नाम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, जिसे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जमा करा दिया जायेगा चूँकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया **। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में 130 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 150 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 25 मीटर पर शेड तथा पूर्व दिशा में 340 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर क्रेशर / प्लांट स्थापित हैं, अतः इसका संपूर्ण विवरण तथा इसके भविष्य में उपयोग के बारे में जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

18. <u>Case No 9771/2023 M/s Shri Dutt Infratech, Partner, Shri Sandeep Bagwala, 1171, Mundi Road, Bijalpur, District-Indore (MP)-452012 Prior Environment Clearance for Ambachandan Stone Quarry in an area of 1.398 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 1033/1, 1033/3 Private) Village-Ambachandan, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1033/1, 1033/3 Private) Village-Ambachandan, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP) 1.398 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप बगवाला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 48 दिनांक 12/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके दक्षिण दिशा में 15 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 380 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर एक आवास / मंदिर हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। आवंटित खनन् क्षेत्र के वन क्षेत्र के समीप होने के कारण ई.एम.पी. में गेमप्रफ फेंसिग का प्रस्ताव ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने अनुशंसा परियोजना प्रस्तावक अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । चूँकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया **। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण दिशा में 15 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 380 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर एक आवास / मंदिर हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र के वन क्षेत्र के समीप होने के कारण ई.एम.पी. में गेमप्रफ फेंसिग का प्रस्ताव ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from

DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets

(separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.

16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall

be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.

17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

.

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर